OPEN ACCESS

Int. Jr. of Contemp. Res. in Multi. *PEER-REVIEWED JOURNAL* *Volume 5 Issue 3 [May- Jun] Year 2026*

Research Article

आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य सुरक्षा एवं सार्क: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. आभा सैनी [1*], डॉ. सुषमा सैनी [2]

[1] प्रोफ़ेसर एवं अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, जैन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुज़फ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, भारत

[2] प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, D.A.V कॉलेज मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, भारत

Corresponding Author: * डॉ. आभा सैनी

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.21332522

सारांश

दक्षिण एशियाई क्षेत्र अपनी प्राकृतिक संसाधन संपन्नता, बढ़ते आर्थिक विकास और विशाल जनसंख्या के कारण वैश्विक स्तर पर एक विशिष्ट पहचान रखता है। हिमालय, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर से घिरा यह क्षेत्र प्राकृतिक, जैविक, जल-संबंधी और मानव-निर्मित आपदाओं के साथ-साथ भारत और पाकिस्तान जैसे परमाणु शक्ति-संपन्न राष्ट्रों की उपस्थिति के कारण परमाणु आपदाओं के जोखिम से भी प्रभावित होता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में की गई, जिसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। प्रस्तुत शोध पत्र में सार्क देशों के बीच आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में हुए पारस्परिक सहयोग का ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक और वर्णनात्मक पद्धति के माध्यम से अध्ययन किया गया है। इसमें सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र, त्वरित प्रतिक्रिया समझौता, सार्क क्षय रोग एवं एचआईवी/एड्स केंद्र, सार्क फूड बैंक, कोविड-19 सूचना विनिमय मंच तथा SAARC वैक्सीन कूटनीति जैसी पहलों का विश्लेषण किया गया है। साथ ही शोध पत्र में सदस्य देशों के बीच राजनीतिक मतभेद, भारत-पाकिस्तान तनाव, 2015 के बाद आपदा प्रबंधन ढांचे के नवीनीकरण में उदासीनता जैसी चुनौतियों को भी रेखांकित किया गया है। अंत में उच्च राजनीतिक इच्छाशक्ति, सामुदायिक भागीदारी, सार्क मौसम विज्ञान अनुसंधान केंद्र के तकनीकी आधुनिकीकरण और एक क्षेत्रीय चिकित्सा भंडार की स्थापना जैसे सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं।

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2583-7397
- **Received:** 05-05-2026
- **Accepted:** 26-06-2026
- **Published:** 30-06-2026
- **IJCRM:**5(3); 2026: 1072-1075
- **©2026, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Article

डॉ. आभा सैनी, डॉ. सुषमा सैनी. आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य सुरक्षा एवं सार्क: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन. Int J Contemp Res Multidiscip. 2026;5(3):1072-1075.

Access this Article Online

www.multiarticlesjournal.com

मूल शब्द: दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क), आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य सुरक्षा, क्षेत्रीय सहयोग, महामारी (कोविड-19)

प्रस्तावना

दक्षिण एशियाई क्षेत्र अपने प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता के कारण और अपने बढ़ते आर्थिक विकास और विशाल जनसंख्या के कारण वैश्विक स्तर पर अपनी एक विशिष्ट पहचान रखता है दक्षिण एशिया, एशिया महाद्वीप का उप क्षेत्र है जिसमें भारत सहित 8 राष्ट्र सम्मिलित हैं सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता लिए हुए यह क्षेत्र अपना एक विशेष भू राजनीतिक महत्व भी रखता है यह क्षेत्र प्राकृतिक और जैविक आपदाओं के कारण प्रभावित होता है हिमालय ,बंगाल की खाड़ी ,अरब सागर और हिंद महासागर का क्षेत्र होने के कारण यह जल संबंधी और मानव निर्मित आपदाओं से भी प्रभावित होता है दो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र भारत और पाकिस्तान होने की वजह से परमाणु आपदाएं भी इस क्षेत्र को प्रभावित करती है इन आपात स्थितियों से निपटने के लिए सार्क देशों के द्वारा आपदा प्रबंधन की व्यवस्था की गई है स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए भी सार्क देशों के बीच

© 2026 डॉ. आभा सैनी, डॉ. सुषमा सैनी . This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

आपसी सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रस्तुत शोध पत्र में इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उनकी भूमिका का अध्ययन किया गया है

साहित्य पुनरावलोकन -

डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल (2006), दक्षिण एशिया की शांति सुरक्षा और विकास के महत्वपूर्ण आयाम पर चर्चा करते हैं वैश्विक दुनिया के संदर्भ में दक्षिण एशिया की भूमिका का वर्णन करते है।

डॉ. एस सी सिंगल (2024) ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में दक्षिण एशियाई देशों की भूमिका और उनके संगठन और चुनौतियों पर चर्चा की है

मार्क जेसन गिल्बर्ट(2017) विश्व इतिहास में दक्षिण एशिया की भूमिका और स्थिति का विश्लेषण करते हैं। डॉ. बी.एल. फादिया (2021) अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सार्क की भूमिका उसके संगठन और कमियो के बारे में वर्णन करते हैं।

इफ्तिखार अहमद, किमोन, टी गजेंद्रन(2020) दक्षिण एशियाई देशों में आपदा के खतरे को कम कैसे किया जा सकता है इसके लिए रणनीतियां को विश्लेषित करते हैं

शोध उद्देश्य और शोध विधि -

प्रस्तुत शोध पत्र में आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य सुरक्षा अवधारणा की व्याख्या की गई है सार्क देशों में आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए किए गए सहयोग का वर्णन किया गया है सार्क देश और उनके द्वारा इस संदर्भ में उठाए गए कदमों का भी विश्लेषण किया गया हैऔर इस संदर्भ में उत्पन्न चुनौतियों और उन समस्याओं के समाधान को भी प्रस्तुत शोध पत्र में प्रस्तुत किया गया है प्रस्तुत शोध पत्र में प्राथमिक और द्वितीय स्रोतों का प्रयोग किया गया है प्रस्तुत शोध पत्र में ऐतिहासिक विश्लेषणात्मक और वर्णनात्मक शोध पद्धति का प्रयोग किया गया है

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन- दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन एक ऐसा मंच है जहां दक्षिण एशियाई क्षेत्र के विभिन्न देश आपस में जनता की आर्थिक ,सामाजिक विकास और कल्याण हेतु विभिन्न क्षेत्र में और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आपस में सहयोग करते हैं सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और उसे मजबूत करना इस संगठन के उद्देश्य में सम्मिलित है भाषा , धार्मिक ,ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आधार पर दक्षिण एशियाई क्षेत्र की राष्ट्रों में समानताएं देखने को मिलती हैं और यही समानता उन्हें एकता के सूत्र में बांधती है विश्व की जनसंख्या का एक बड़ा भाग इस क्षेत्र में निवास करता है और इसकी भू राजनीतिक स्थिति विश्व में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है दक्षिण एशिया क्षेत्र के देश की सीमाएं अफगानिस्तान को छोड़कर आपस में एक दूसरे के साथ लगती है भारत के साथ लगभग सभी देश भाषाई सांस्कृतिक ऐतिहासिक और धार्मिक समानता रखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में भारत और पाकिस्तान ब्रिटिश साम्राज्य की अधीनता में रह चुके हैं श्रीलंका और मालदीव ब्रिटिश राज से स्वतंत्र थे औपनिवेशिक सरकारों के द्वारा नियंत्रित होते थे

सार्क में आठ सदस्य देश भारत पाकिस्तान नेपाल भूटान बांग्लादेश श्रीलंका मालदीव्स अफगानिस्तान सम्मिलित है दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग का विचार सर्वप्रथम नवंबर 1980 में सामने आया था। सात संस्थापक देशों- बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका के विदेश सचिवों के परामर्श के बाद इनकी प्रथम मुलाकात अप्रैल 1981 में कोलंबिया में हुई थी। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (The South Asian Association for Regional Cooperation-SAARC) की स्थापना 8 दिसंबर,1985 को ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी।अफगानिस्तान वर्ष 2005 में आयोजित हुए 13वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में सार्क का सबसे नया सदस्य बना। संगठन का मुख्यालय एवं सचिवालय नेपाल के काठमांडू में अवस्थित है। वर्तमान में सार्क के 9 पर्यवेक्षक सदस्य देश हैं- ऑस्ट्रेलिया, चीन ,यूरोपियन यूनियन , ईरान, जापान ,रिपब्लिक ऑफ कोरिया , मॉरीशस , म्याँमार एवं संयुक्त राज्य अमेरिका हैं

सार्क देशों का अपना एक चार्टर है चार्टरके अनुच्छेद एक में इसके उद्देश्य और दो में सिद्धांतों का वर्णन किया गया है इसके सिद्धांतों में सहयोग सामान्य क्षेत्रीय अखंडता राजनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखना एक दूसरे का सहयोग करना दीपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग है अनुच्छेद 3 में प्रति वर्ष में होने वाले शिखर सम्मेलनों का वर्णन किया गया है सार्क के अब तक कुल 18 सम्मेलन हो चुके हैं अनुच्छेद 4 में सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की मंत्री परिषद का वर्णन है 5 6 और 7 स्थाई और तकनीकी और कार्यकारी समिति के बारे में बताते हैं अनुच्छेद 8 में इसकी सचिवालय का वर्णन किया गया है महासचिव का पद सदस्य देशों में बारी-बारी से जाता है प्रत्येक सदस्य देश वित्तीय अंशदान देता है

आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्यसुरक्षा - प्राकृतिक आपदाओं में प्रकृति से उत्पन्न होने वाली आपदा सम्मिलित है जिनमें विनाशकारी भूकंप बाढ़ सूखा चक्रवात जैसी आपदाएं शामिल है और जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के देश को प्रभावित कर रहे हैं और इस कारण उनका आर्थिक विकास भी प्रभावित हो रहा है प्राकृतिक आपदाओं के अतिरिक्त मानव निर्मितआपदाएं भी हैं जिसमें औद्योगिक दुर्घटना, आतंकवादी हमले ,परमाणु और रासायनिक हथियारों से उत्पन्न आपदाएं भी सम्मिलित है इन आपदाओं से निपटना इनकी पहले से ही रोकथाम तैयारी करना और प्रतिक्रिया और पुनरप्राप्ति के लिए संसाधनों का संगठन और प्रबंधन आपदा प्रबंधन में सम्मिलित है इसमें नीतियां बनाना जागरूकता फैलाना आपदा आने पर तत्काल बचाव कार्य पुनर्निर्माण और पुनर्वास की प्रक्रिया सम्मिलित है जिसमें केंद्रीय राज्य और स्थानीय स्तर पर सहयोग एवं संबंध जरूरी हो जाता है आपदा आने से पूर्व रोकथाम की प्रक्रिया भी इसमें सम्मिलित है जिसमें नीति निर्माण के लिए निर्माण मानक और नियमों को बनाना और लागू करना एवं जागरूकता फैलाना आपदाओं का पूर्वानुमान लगाना और जनता को इसके लिए पहले से ही चेतावनी देना ,आपदा प्रबंधन के लिए योजनाएं बनाना और आवश्यक संसाधन की तैयारी रखना जैसे जीवन रक्षा किट इत्यादि की व्यवस्था पहले से ही रखना आपदा प्रबंधन टीमों को प्रशिक्षित करना और उन्हें पहले ही तैयार रखना आपदा प्रबंधन में सम्मिलित है

मानव स्वास्थ्य सुरक्षा में शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा दोनों ही सम्मिलित होते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसारपूरी तरह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य की सुरक्षा सिर्फ़ बीमारी या कमज़ोरी का न होना नहीं, बल्कि एक पूरे नज़रिए पर ज़ोर देना जिसमें ज़िंदगी में ढलने की काबिलियत और अच्छे से काम करना

© 2026 डॉ. आभा सैनी, डॉ. सुषमा सैनी . This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

शामिल है, जो सिर्फ़ शारीरिक काम से आगे बढ़कर रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए अच्छी सेहत और रिसोर्स को शामिल करता है।

सार्क देशों के मध्य आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ सहयोग-

सार्क ने आपदा प्रबंधन और पर्यावरण को प्राथमिकता प्रदान की है जिसमें आपसी ज्ञान साझा करने पर जोर दिया गया है सार्क देशों ने 1987 से लगातार शिखर सम्मेलनों के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं को न्यूनतम करने की आवश्यकता पर जोर दिया है सार्क ने आपदाएं इस क्षेत्र में कम से कम हो इसके लिए 2005 से 2015 के बीच में अनेक योजनाएं बनाई 2011 में प्राकृतिक आपदाओं पर नियंत्रण करने के लिए एक त्वरित प्रतिक्रिया समझौता भी किया गया इस क्षेत्र में दूसरा महत्वपूर्ण कदम सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र मंच की स्थापना है जो ज्ञान अनुसंधान और क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करता है और सदस्य देशों को लाभ पहुंचता है

सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र नीतिगत सलाह प्रदान करने और प्रभावी आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के लिए रणनीतिक शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण, प्रणाली विकास, विशेषज्ञता संवर्धन और सूचना के आदान-प्रदान सहित क्षमता निर्माण को सुगम बनाने के लिए केंद्र के अधिदेश का विस्तार करके इसमें एक प्राकृतिक आपदा त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र का विकास भी शामिल किया गया सार्क पर्यावरण मंत्रियों ने पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं के क्षेत्र में प्रगति का जायजा लेने और क्षेत्रीय सहयोग को और बढ़ाने के लिए समय-समय पर बैठकें की हैं। 1992 से, सार्क पर्यावरण मंत्रियों की नौ बार बैठकें हो चुकी हैं। सितंबर 2011 के बाद से सार्क पर्यावरण मंत्रियों की कोई बैठक नहीं हुई है।

सार्क कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग कर रहा है और जुलाई 2004 में दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम (SACEP), जून 2007 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP), सितंबर 2008 में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण रणनीति (UNISDR) और एशिया आपदा तैयारी केंद्र (ADPC) के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर कर चुका है। आवश्यकतानुसार इन समझौता ज्ञापनों का नवीनीकरण किया जाता है। ये एजेंसियाँ सार्क कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं।2016 से लागू सार्क देशों समझौते का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के मध्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान त्वरित राहत और बचाव कार्यों में सहयोग करना है।

इसके अतिरिक्त, सार्क देशों ने कोविद-19 के समय आपातकालीन कोष की भी स्थापना की हिंद महासागर सुनामी के बाद पर्यावरण मंत्रियों का एक विशेष सत्र जुलाई 2005 में माले में आयोजित किया गया था और जलवायु परिवर्तन पर सार्क मंत्रिस्तरीय बैठक जुलाई 2008 में ढाका में आयोजित की गई थी भारत के नेतृत्व में आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक पहल आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन शुरू की गई है, जिसमें सार्क क्षेत्र के कई देश सदस्य हैं और यह क्षेत्रीय जलवायु चुनौतियों से निपटने में सहायक है। सार्क के तहत एक क्षेत्रीय आपदा प्रतिक्रिया तंत्र विकसित किया गया है, जिसके तहत प्रभावित देश की संप्रभुता का सम्मान करते हुए केवल अनुरोध पर ही अन्य सदस्य देश राहत सामग्री भेजते हैं।दक्षिण एशियाई वार्षिक आपदा प्रबंधन अभ्यास (SAADMEx) भारत के नेतृत्व में एक नियमित सिमुलेशन अभ्यास है। इसके तहत सदस्य देशों की सेनाएं और राहत एजेंसियां (जैसे भारत की NDRF) संयुक्त रूप से खोज, बचाव और राहत कार्यों का पूर्वाभ्यास करती हैंसार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा करना आपदा सुरक्षित सेवाओं का वितरण ढांचा सुनिश्चित करना स्वास्थ्य जोखिमों को कम करना रोकथाम आधारित दृष्टिकोण पर जोर देना सहयोग में सम्मिलित है

कोविद-19 महामारी के दौरान वैक्सीन कूटनीति भी सार्क सदस्य देशों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है ।सार्क का उद्देश्य इस क्षेत्र में आने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और उनके स्वास्थ्य सुरक्षा को भी ध्यान में रखना है इसीलिए यह स्वास्थ्य सेवाओं की सही समय पर उपलब्धता करना भी उनकी रणनीति का एक हिस्सा है आपदा में बच्चों की देखभाल और भागीदारी पर सार्क ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन कराया दसवीं सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान स्वास्थ्य एवं पोषण संवर्धन को सामाजिक चार्ट में सम्मिलित किया गया

सार्क क्षय रोग केंद्र (एसटीसी) की स्थापना 1992 में राष्ट्रीय कार्यक्रमों के प्रयासों के समन्वय द्वारा क्षेत्र में क्षय रोग की रोकथाम और नियंत्रण में सदस्य देशों की सहायता के लिए की गई थी। 2005 में इस केंद्र का नाम बदलकर सार्क क्षय रोग और एचआईवी/एड्स केंद्र (एसटीएसी) कर दिया गया। टीबी और एचआईवी/एड्स से संबंधित क्षेत्रीय गतिविधियों के समन्वय और कार्यान्वयन की ज़िम्मेदारी एसटीएसी को सौंपी गई है। केंद्र ने सचिवालय और संयुक्त राष्ट्र के सहयोगियों के साथ मिलकर एचआईवी/एड्स पर सार्क क्षेत्रीय रणनीतियाँ विकसित की हैं, जो एचआईवी/एड्स की रोकथाम के लिए क्षेत्रीय प्रयासों के समन्वय में केंद्र के कार्य का मार्गदर्शन करती हैं।

गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम (SARS) के उभरने से उत्पन्न व्यापक खतरों के मद्देनजर, इस घातक महामारी से निपटने हेतु एक क्षेत्रीय रणनीति विकसित करने हेतु अप्रैल 2003 में माले में सार्क स्वास्थ्य मंत्रियों की एक आपात बैठक आयोजित की गई थी। इस एक दिवसीय बैठक में क्षेत्र में SARS के प्रसार को रोकने और नियंत्रित करने के उपाय करने के साथ-साथ प्रवेश बिंदुओं पर स्क्रीनिंग, संभावित SARS रोगियों को संगरोध या अलगाव केंद्रों में स्थानांतरित करने और प्रभावी संपर्क अनुरेखण सुनिश्चित करने जैसे व्यापक निवारक उपाय अपनाने का निर्णय लिया गया। मंत्रियों ने SARS के प्रति सामूहिक SAARC प्रतिक्रिया पर माले घोषणापत्र को अपनाया।

स्वास्थ्य मंत्रियों ने अपनी पहली बैठक में सार्क सदस्य देशों के बीच स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया, न केवल पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र में, बल्कि क्षेत्र के समक्ष उपस्थित सभी स्वास्थ्य समस्याओं पर भी। उन्होंने उभरती और फिर से उभरती बीमारियों की समस्या के समाधान के लिए अंतर-देशीय सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया। उन्होंने सार्क सदस्य देशों के बीच विशेषज्ञता के आदान-प्रदान और अवसंरचनात्मक सुविधाओं को

© 2026 डॉ. आभा सैनी, डॉ. सुषमा सैनी . This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

साझा करके निगरानी, रिपोर्टिंग, निदान और प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने का आह्वान किया। बैठक में एचआईवी/एड्स, टीबी और अन्य घातक संक्रामक रोगों से निपटने के लिए एक साझा क्षेत्रीय रणनीति विकसित करने के महत्व पर बल दिया गया और एक सार्क निगरानी केंद्र और एक त्वरित तैनाती स्वास्थ्य प्रतिक्रिया प्रणाली स्थापित करने की भी सिफारिश की गई। सार्क स्वास्थ्य मंत्रियों की लगातार हर वर्ष बैठकर आयोजित की गई जिसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई

सार्क के स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए सार्क कोविड-19 सूचना विनिमय मंच विकसित किया गया, जिसका उद्देश्य महामारी से जुड़े डेटा और तकनीकों का वास्तविक समय में आदान-प्रदान करना है।सार्क फूड बैंक (SAARC Food Bank)आपदा या स्वास्थ्य आपातकाल के समय उत्पन्न होने वाले खाद्य संकट से निपटने के लिए बैंक की स्थापना की गई है, जो आपात स्थिति में सदस्य देशों को खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करता है रोग निगरानी और स्वास्थ्य कूटनीति के माध्यम से सार्क देशों के बीच जूनोटिक रोगों (पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारियां) और संक्रामक रोगों की निगरानी के लिए सूचनाओं का आदान-प्रदान भी किया जाता है।

मुद्दे एवं चुनौतियां

सार्क देशों के मध्य आपसी राजनीतिक मतभेद जारी है जिसकी वजह से यह उनके सहयोग में चुनौती बन जाता है जलवायु परिवर्तन के कारण भी आपसी सहयोग चुनौती पूर्ण हो जाता है भारत और पाकिस्तान के मध्य लगातार विवाद बने रहना सार्क देशों के बीच सहयोग को कम करता है 2015 के बाद आपदा प्रबंधन का नवीनीकरण न होना और इस मुद्दे के प्रति सदस्य देशों की उदासीनता एक महत्वपूर्ण चुनौती बन जाती है भारत इन देशों में एक शक्तिशाली और विशाल राष्ट्र है इसी वजह से छोटे राष्ट्रों से शंका और विश्वास की दृष्टि से देखते हैं विश्व की जनसंख्या का 21% राज्य है विश्व के क्षेत्रफल का तीन प्रतिशत भूभाग इस क्षेत्र में स्थित है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में यह क्षेत्र अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है बड़े और शक्तिशाली और महाशक्तियों का दक्षिण एशियाई क्षेत्र में लगातार अपना वर्चस्व और प्रभुत्व बनाए रखने की कोशिश करना इस क्षेत्र की भू राजनीतिक स्थिति और बढ़ते महत्व के कारण और अधिक हो जाता है जिससे कि इन देशों में आपस में मनमुटाव और संघर्ष बना रहता है और संवाद की कमी पाई जाती है

निष्कर्ष एवं सुझाव

उच्च राजनीतिक इच्छा शक्ति का होना ,सीमा पर सहयोग और आपदा प्रबंधन के लिए सभी देश का एकजुट होना और उदासीन ना होना जरूरी हो जाता है आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में सामुदायिक क्षेत्र की भागीदारी भी अनिवार्य हो जाती है मौसम संबंधी विशेष घटनाओं और संभावित आपदाओं की सटीक जानकारी के लिए 'सार्क मौसम विज्ञान अनुसंधान केंद्र' (SMRC) का तकनीकी आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए । किसी भी स्वास्थ्य आपातकाल या महामारी के समय जरूरी दवाओं, टीकों और आवश्यक उपकरणों की निर्बाध आपूर्ति के लिए एक 'सार्क क्षेत्रीय चिकित्सा बैंक' (Regional Medical Reserve) स्थापित किया जाना चाहिए।

सन्दर्भ सूची

1. अग्रवाल P. *South Asia: Peace, Security and Development*. नई दिल्ली: कैलाश बुक्स पब्लिकेशन; 2006.
2. फढ़िया BL. *अंतरराष्ट्रीय राजनीति*. आगरा: साहित्य भवन पब्लिकेशन; 2021.
3. सिंगल SC. *अंतरराष्ट्रीय राजनीति*. आगरा: लक्ष्मीनारायण अग्रवाल; 2024.
4. अहमद I, Kimon T, गजेंद्रन T. *Disaster Resilience in South Asia*. New York: Routledge; 2020.
5. Gilbert MJ. *South Asia in World History*. New York: Oxford University Press; 2017.
6. पंत P, जैन SP. *अंतरराष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत और व्यवहार*. मेरठ: मीनाक्षी प्रकाशन; 2003.
7. United Nations Development Programme. *Human Development Report 2023/2024*. New Delhi: Oxford University Press; 2024.
8. South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC). SAARC official website [Internet]. Kathmandu: SAARC Secretariat; [cited 2026 Jul 9]. Available from: https://saarc-sec.org
9. *The Hindu*. Official website. Chennai: Kasturi & Sons Ltd. Available from: https://www.thehindu.com

Creative Commons (CC) License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution–Non-Commercial–No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. This license permits sharing and redistribution of the article in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted under this license.

About the Author

डॉ. आभा सैनी जैन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुज़फ्फरनगर के राजनीति विज्ञान विभाग में प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हैं। उन्हें शिक्षण, शोध तथा अकादमिक प्रशासन का व्यापक अनुभव है। उनकी विशेषज्ञता राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, शासन एवं अंतरराष्ट्रीय संबंधों में है। उन्होंने अनेक शोधपत्र प्रकाशित किए हैं तथा विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों में सहभागिता की है।

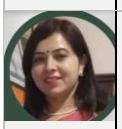

डॉ. सुषमा सैनी डी.ए.वी. कॉलेज, मुज़फ्फरनगर के अर्थशास्त्र विभाग में प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हैं। उन्हें अर्थशास्त्र, विकास अध्ययन तथा सार्वजनिक नीति के क्षेत्र में व्यापक शिक्षण एवं शोध अनुभव प्राप्त है। उन्होंने अनेक शोधपत्र प्रकाशित किए हैं तथा विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक कार्यक्रमों में सक्रिय सहभागिता निभाई है।

© 2026 डॉ. आभा सैनी, डॉ. सुषमा सैनी . This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/